केन्द्रीय सूचना आयोग
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग,मुनिरका
Baba Gangnath Marg, Munirka
नई दिल्ली, New Delhi – 110067

द्वितीय अपील संख्या / Second Appeal No. **(As Per Annexure)**

Kamal Nagar ... अपीलकर्ता/Appellant

VERSUS
बनाम

CPIO: University Grants Commission, New Delhi ...प्रतिवादीगण/Respondent

Relevant dates emerging from the appeal(s):

Sl. No.	Second Appeal No.	Date of RTI Application	Date of CPIO's Reply	Date of First Appeal	Date of FAA's Order	Date of Second Appeal
1.	105269	05.07.2023	08.08.2023	31.08.2023	Nil	13.02.2024
2.	105342	12.07.2023	14.08.2023	31.08.2023	14.10.2023	13.02.2024
3.	105330	11.07.2023	20.07.2023	31.08.2023	03.10.2023	13.02.2024
4.	105386	10.07.2023	10.08.2023	31.08.2023	Nil	13.02.2024
5.	105264	03.07.2023	28.07.2023	31.08.2023	14.10.2023	13.02.2024
6.	105265	03.07.2023	28.07.2023	31.08.2023	14.10.2023	19.02.2024

The instant set of appeals have been clubbed for decision as these relate to similar RTI Applications and same subject matter.

Date of Hearing: 12.03.2025
Date of Decision: 21.03.2025

CORAM:
Hon'ble Commissioner
ANANDI RAMALINGAM

O R D E R

Second Appeal No. CIC/UPSCM/A/2024/105269

1. The Appellant filed an RTI application dated 05.07.2023 seeking information on the following points:

- *वर्ष 2021 एवं 2022 में मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति के संबंध में दिनांक सिलेक्शन कमेटी की बैठक माह मई 2023 में आयोजित हुई थी। जिसमें अधोहस्ताक्षरकर्ता का नाम भी प्रस्तावित था परंतु डी.ओ.पी.टी द्वारा जारी अधिसूचना में अधोहस्ताक्षरकर्ता का चयन माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने के दृष्टिगत नहीं किया गया। कृपया अधोहस्ताक्षरकर्ता के संबंध में निम्न दस्तावेज प्रदाय करने का कष्ट करें-*

1. *वर्ष 2021 की रिक्तियों के संबंध में सिलेक्शन कमेटी द्वारा तैयार Minutes of the meeting*
2. *वर्ष 2022 की रिक्तियों के संबंध में सिलेक्शन कमेटी द्वारा तैयार Minutes of the meeting*
3. *वे दस्तावेज / कारण जिसके आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता का चयन वर्ष 2021 की रिक्तियों के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा में नहीं किया गया के संबंध में समस्त दस्तावेज ।*
4. *वे दस्तावेज / कारण जिसके आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता का चयन वर्ष 2022 की रिक्तियों के संबंध में भारतीय प्रशासनिक सेवा में नहीं किया गया के संबंध में समस्त दस्तावेज ॥*
5. *अधोहस्ताक्षरकर्ता को अनफिट किये जाने के संबंध में दस्तावेज ।*

…, etc./ other related information

1.1. The CPIO replied vide letter dated 08.08.2023 and the same is reproduced as under :-

"With regard to the information sought at points (1) & (2) of the RTI application, it is informed that requisite information has already provided to you vide CPIO's reply dated 24.07.2023. However, a certified copy of the minutes comprising 20 pages is enclosed herewith.

With regard to the information sought at point (3) to (9) of the RTI application, it is informed that the information sought pertains to the State Government. You are, therefore, advised to approach the State Government, in this regard."

1.2. Dissatisfied with the response received from the CPIO, the Appellant filed a First Appeal dated 31.08.2023 alleging that the information provided was incomplete, false and misleading. The FAA vide order dated Nil upheld the reply given by the CPIO.

1.3. Aggrieved with the FAA's order, the Appellant approached the Commission with the instant Second Appeal dated 13.02.2024.

Second Appeal No. CIC/UPSCM/A/2024/105342

2. The Appellant filed an RTI application dated 12.07.2023 seeking information on the following points:

1. *अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 28.04.2023 को चैयरमेन संघ लोक सेवा आयोग को मय समस्त दस्तावेज सहित अभ्यावेदन प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक द्वारा दुर्भावनापूर्वक कार्यवाही की जा रही है व उसके संबंध में समस्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये थे तथा निवेदन किया गया था कि अभ्यावेदन एवं दस्तावेजों के अनुक्रम में-*

   • सामान्य प्रशासन विभाग मध्यप्रदेश को निर्देशित किया जाये कि तथ्यों के सापेक्ष यदि उनके द्वारा प्रतिकूल प्रस्ताव प्रेषित किये गये हैं तो उन्हें संशोधित किया जाये।

   • नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुक्रम में अनुरोध किया गया था कि यदि सामान्य प्रशासन विभाग कार्मिक द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी/दस्तावेज़ प्रेषित किये गये हो तो उक्त

जानकारी / दस्तावेज प्रदाय करे ताकि अधोहस्ताक्षरकर्ता संघ लोक सेवा आयोग को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सके।

• प्रमुख सचिव कार्मिक सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध दुर्भावनापूवर्क कार्यवाही की गई है उनको न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पक्षकार भी बनाया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा प्रस्तुत डब्ल्यूपी प्रथम दृष्टया युक्तियुक्त पाये जाने से प्रमुख सचिव कार्मिक द्वारा युक्तियुक्त कार्यवाही पर स्थगन भी दिया गया है। अतः नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुक्रम में SCM में प्रमुख सचिव कार्मिक का होना युक्तियुक्त नहीं है इसलिए एससीएम का कंपोजीसन परिवर्तित किया जाये।.......

उपरोक्तानुसार अवगत कराया जाकर पदोन्नति की कार्यवाही करने, इंटीग्रिटी जारी करने तथा यदि कोई नकारात्मक प्रस्ताव भेजा गया है तो उसे नियमानुसार सुधार कर पदोन्नति संबंधी आगामी कार्यवाही का अनुरोध किया गया था।

कृपया उपरोक्त अभ्यावेदन के संबंध में कृत कार्यवाही विषयक नस्ती मय संपूर्ण दस्तावेज।

…, etc./ other related information

2.1. The CPIO replied vide letter dated 14.08.2023 and the same is reproduced as under :-

"With regard to the information sought at points (1) to (4) of the RTI application, it is informed that the representations received directly from the State Service Officer are not entertained. However, the requisite information on your representations have already provided to you under RTI Act, 2005 vide CPIO's letter dated 24.07.2023."

2.2. Dissatisfied with the response received from the CPIO, the Appellant filed a First Appeal dated 31.08.2023 alleging that the information provided was incomplete, false and misleading. The FAA vide order dated 14.10.2023 upheld the reply given by the CPIO.

2.3. Aggrieved with the FAA's order, the Appellant approached the Commission with the instant Second Appeal dated 13.02.2024.

Second Appeal No. CIC/UPSCM/A/2024/105330

3. The Appellant filed an RTI application dated 11.07.2023 seeking information on the following points:

1. *अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 16.05.2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अवगत कराया गया था कि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा स्थगन / अधोहस्ताक्षरकर्ता के विरूद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं किये जाने के निर्णय के पश्चात् भी यदि सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा कोई ऐसी कार्यवाही प्रस्तावित की गई है या विभाग के स्तर पर प्रचलित है जैसे इंटीग्रिटी सटिर्फिकेट तो कृपया तादाशय की जानकारी से नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के अनुक्रम में अवगत कराने का कष्ट करें। उक्त आवेदन की प्रति संघ लोक सेवा आयोग तथा मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन को भी प्रदाय की गई प्रदाय का थी। उक्त आवेदन विषयक कृत कार्यवाही के संबंध में संधारित नस्ती मय संपूर्ण दस्तावेज ।*
2. *अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 29.04.2023 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर अनुरोध किया गया था कि सामान्य प्रशासन विभाग, कार्मिक द्वारा वांछित जानकारी प्रदाय नहीं की गई है जिसकी प्रति संघ लोक सेवा आयोग तथा मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन को भी प्रदाय की गई थी। उक्त आवेदन विषयक कृत कार्यवाही के संबंध में संधारित नस्ती मय संपूर्ण दस्तावेज ।*
3. *अधाहस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 27.04.2023 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की प्रति संलग्न कर अनुरोध किया गया था कि यदि उक्त निर्णयों के पश्चात् ऐसा कोई कारण नहीं है जिसके आधार पर अधोहस्ताक्षरकर्ता की पदोन्नति रोकी जायें (गोपनीय चरित्रावली / इंटीग्रिटी के आधार पर)। उक्त आवेदन की प्रति संघ लोक सेवा आयोग तथा*

मंत्रालय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन को भी प्रदाय की गई थी। उक्त आवेदन विषयक कृत कार्यवाही के संबंध में संधारित नस्ती मय संपूर्ण दस्तावेज ।

…, etc./ other related information

3.1. The CPIO replied vide letter dated 20.07.2023 and the same is reproduced as under :-

"Shri Kamal Chandra Nagar के दिनांक 11.07.2023 के आर.टी.आई. आवेदन को सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत State Government of Madhya Pradesh and Union Public Service Commission को हस्तांतरित किया जा रहा है चूंकि मांगी गयी सूचना की विषयवस्तु का संबंध State Government of Madhya Pradesh and Union Public Service Commission से है। अतः आर.टी.आई. आवेदन को संबंधित विभाग में भेजा जा रहा है। तथा साथ ही में आपके आर टी आई पत्र को इस विभाग के केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को भी भेजा गया है।"

3.2. Dissatisfied with the response received from the CPIO, the Appellant filed a First Appeal dated 31.08.2023 alleging that the information provided was incomplete, false and misleading. The FAA vide order dated 03.10.2023 upheld the reply given by the CPIO.

3.3. Aggrieved with the FAA's order, the Appellant approached the Commission with the instant Second Appeal dated 13.02.2024.

Second Appeal No. CIC/UPSCM/A/2024/105386

4. The Appellant filed an RTI application dated 10.07.2023 seeking information on the following points:

1. *गोपनीय प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रतिकूल टिप्पणी स संसूचित किये जाने के संबंध में भारत सरकार/संघ लोक सेवा आयोग / मध्यप्रदेश शासन द्वारा आज दिनांक तक जारी किये गये समस्त अधिनियम / नियम / निर्देश/परिपत्र जिनमें गोपनीय प्रतिवेदन में उल्लेखित प्रतिकूल टिप्पणी/ ग्रेड संसूचित किये जाने, सूचित किये जाने की समय-सीमा, समय-सीमा*

में सूचित नहीं करने पर, क्या प्रभाव होंगे, सूचित किये जाने पर अभ्यावेदन किये जाने की समय-सीमा.. अभ्यावेदन का निराकरण किये जाने की समय-सीमा, प्रतिकूल टिप्पणी नहीं करने पर/अभ्यावेदन का निराकरण नहीं होने तक पदोन्नति पर क्या प्रभाव होंगे संबंधी समस्त दस्तावेज जिसके आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग / संघ लोक सेवा आयोग/भारत सरकार कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय द्वारा पदोन्नति के संबंध में कार्यवाही की जाती है।

2. *उक्त नियमों के सापेक्ष क्या अधोहस्ताक्षरकर्ता को कोई प्रतिकूल टिप्पणी संसूचित की गई विषयक दस्तावेज।*
3. *उक्त नियमों के सापेक्ष क्या अधोहस्ताक्षरकर्ता के अभ्यावेदन का अवसर दिया गया तत्विषयक दस्तावेज।*
4. *पदोन्नति से पहले भी अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा क्या उसे कभी भी प्रतिकूल टिप्पणी से संसूचित किया गया हो संबंधी जानकारी चाही गई थी तत्विषयक दस्तावेज ।*
5. *अधोहस्ताक्षरकर्ता के उक्त पत्र/अभ्यावेदन के संबंध सामान्य प्रशासन विभाग/भारत सरकार, कार्मिक एवं पेंशन मंत्रालय / संघ लोक सेवा आयोग द्वारा कृत कार्यवाही के संबंध में संधारित नस्ती / संपूर्ण दस्तावेज ।*

…, etc./ other related information

4.1. The CPIO replied vide letter dated 10.08.2023 and the same is reproduced as under :-

> *"With regard to the information sought at point (1) to (6) of the RTI application, it is informed that the information sought pertains to the State Government. You are, therefore, advised to approach the State Government, in this regard."*

4.2. Dissatisfied with the response received from the CPIO, the Appellant filed a First Appeal dated 31.08.2023 alleging that the information provided was incomplete, false and misleading. The FAA vide order dated Nil upheld the reply given by the CPIO.

4.3. Aggrieved with the FAA's order, the Appellant approached the Commission with the instant Second Appeal dated 13.02.2024.

Second Appeal No. CIC/UPSCM/A/2024/105264

5. The Appellant filed an RTI application dated 03.07.2023 seeking information on the following points:

1. *भारत सरकार द्वारा इन्टीग्रिटी सर्टिफिकेट जारी किये जाने / with hold किये जाने के संबंध में जारी समस्त परिपत्र / सरकुलर / दस्तावेज जिसके आधार पर संघ लोक सेवा आयोग को राज्य शासन द्वारा इन्टीग्रिटी जारी की जाती है/रोकी जाती है।*
2. *सचिव संघ लोक सेवा आयोग को मेरे द्वारा अभ्यावेदन एवं मेल दिनांक 27.4.2023 के संबंध में आयोग द्वारा कृत कार्यवाही विषयक संधारित नस्ति मय संपूर्ण दस्तावेज ।*
3. *चेयरमेन संघ लोक सेवा आयोग को मेरे द्वारा अभ्यावेदन दिनांक 28.4.2023 एवं मेल दिनांक 29.4.2023 के संबंध में आयोग द्वारा कृत कार्यवाही विषयक संधारित नस्ति मय संपूर्ण दस्तावेज ।*
4. *सचिव संघ लोक सेवा आयोग को प्रेषित अभ्योवदन दिनांक 16.5.2023 एवं मेल दिनांक 17.5.2023 के संबंध में आयोग द्वारा कृतं कार्यवाही विषयक संधारित नस्ति मय संपूर्ण दस्तावेज।*
5. *सचिव संघ लोक सेवा आयोग को प्रेषित पत्र एवं मेल दिनांक 17.5.23 के संबध में आयोग द्वारा कृत कार्यवाही विषयक संधारित नस्ति मय संपूर्ण दस्तावेज।*

…, etc./ other related information

5.1. The CPIO replied vide letter dated 28.07.2023 and the same is reproduced as under :-

"With regard to the information sought at point (1) of the RTI application, it is informed that the information sought is not specific & clear.

With regard to the information sought at points (2) to (6) of the RTI application, it is informed that the representations received directly from the State Service Officer are not entertained. However, the requisite information on your representations have already provided to you under RTI Act, 2005 vide CPIO's letter dated 24.07.2023."

5.2. Dissatisfied with the response received from the CPIO, the Appellant filed a First Appeal dated 31.08.2023 alleging that the information provided was incomplete, false and misleading. The FAA vide order dated 14.10.2023 upheld the reply given by the CPIO.

5.3. Aggrieved with the FAA's order, the Appellant approached the Commission with the instant Second Appeal dated 13.02.2024.

<u>Second Appeal No. CIC/UPSCM/A/2024/105265</u>

6. The Appellant filed an RTI application dated 03.07.2023 seeking information on the following points:

1. *अधोहस्ताक्षरकर्ता की राज्य प्रशासनिक सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवा में पदोन्नति, वर्ष 2021 एवं 2022 मे कारित रिक्तियों के परिपेक्ष्य में संभावित थी परन्तु यह ज्ञात हुआ है कि 2024 मैं अधोहस्ताक्षरकर्ता को unfit कर दिया गया है। अधोहस्ताक्षरकर्ता को पूरे केरियर के दौरान कभी भी एडवर्स रिमार्कस सूचित नहीं किया गया है। अतः जिस वर्ष के लिए unfit किया गया है उस वर्ष के संबंध में एडवर्स रिर्माक सूचित किये जाने के संबध में राज्य शासन द्वारा संघ लोक सेवा आयोग को प्रेषित दस्तावेज ।*
2. *यदि उन वर्षों के लिए मेरी इन्टीग्रिटी जारी की गई हो या रोकी गई हो तो रोकने/जारी करने संबंधी दस्तावेज ।*
3. *इन्टीग्रिटी सर्टिफिकेट जारी किये जाने/रोकें जाने के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी निम्न दस्तावेजः-*

   1- Instruction No. 14/23/65-AIS(III) dated 28-7-1966.

2- No. 17/3/70-AIS(III) dated 26-5-1970

3- No. 14015/18/99-AIS dated 27-10-1999 & F 14015/18/99 AIS(III) dated 27-10-2001.

जिसके आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा पदोन्नति के संबंध में कार्यवाही की जाती है।

…, etc./ other related information

6.1. The CPIO replied vide letter dated 28.07.2023 and the same is reproduced as under :-

"With regard to the information sought at points (1) & (2) of the RTI application, it is informed that the information sought pertains to the State Government. You are, therefore, advised to approach the State Government, in this regard.

With regard to the information sought at point (3) of the RTI application, it is informed that the Order No. 14/23/65-AIS(III) dated 28.07.1966 & No.17/3/70-AIS(III) dated 26.05.1970 pertain to Ministry of Home Affairs and Order No.14015/18/99 dated 27.10.99 & F.No.14015/18/99-AIS(III) dated 27.10.2001 pertains to DOP&T. You are advised to approach the concerned Ministry in this regard."

6.2. Dissatisfied with the response received from the CPIO, the Appellant filed a First Appeal dated 31.08.2023 alleging that the information provided was incomplete, false and misleading. The FAA vide order dated 14.10.2023 upheld the reply given by the CPIO.

6.3. Aggrieved with the FAA's order, the Appellant approached the Commission with the instant Second Appeal dated 19.02.2024.

<u>Hearing proceedings and Decision:-</u>

7. The appellant attended the hearing through video conference and on behalf of the respondent Mr. Nand Kishor Kumar, Dy. Secretary, Mr. Sanjay Kumar, CPIO and Mr. Madhur Bhaskar, S.O attended the hearing in-person.

8. The appellant *inter alia* submitted that complete information has not been provided till date. He stated that he has sought copies of documents which have been forwarded by the State Government to the respondent for selection and requested the Commission to direct the respondent to furnish the information as sought.

9. The respondent while defending their case *inter alia* submitted that all the RTI applications are related to the SCM for preparation of select list of 2021 and 2022 for promotion of SCS officers Madhya Pradesh to the IAS. He stated that all available information like copy of minutes comprising 20 pages have been provided to the appellant vide letters dated 08.08.2023, 14.08.2023, 20.07.2023, 10.08.2023 and 28.07.2023. Moreover, remaining information that is sought are all non-specific and hence, the appellant has been advised to approach State Government concerned. He submitted that on same subject matter the Hon'ble Commission vide file no. CIC/UPSCM/C/2023/133197 disposed of the matter.

10. The Commission after adverting to the facts and circumstances of the case, hearing both parties and perusal of records, observes that the CPIO has provided appropriate replies to the RTI Applications vide letters dated 08.08.2023, 14.08.2023, 20.07.2023, 10.08.2023 and 28.07.2023. Moreover, on the same subject matter, the Commission vide file nos. CIC/UPSCM/C/2023/133197, CIC/UPSCM/C/2023/138375 and CIC/UPSCM/A/2023/138369, has already decided the matters. The perusal of the RTI applications further reveals that the appellant has sought clarification, interpretation and opinion, which do not fall within the definition of "information" as defined under section 2 (f) of the RTI Act. In this regard, the attention of the appellant is also drawn towards a judgment of the Hon'ble Supreme Court in ***Central Board of Secondary Education &Anr. vs. Aditya Bandopadhyay & Ors*** **[Civil Appeal No.6454 of 2011]** date of judgment 09.08.2011. The following was thus held:

> "….*A public authority is also not required to furnish information which require drawing of inferences and/or making of assumptions. It is also not required to provide 'advice' or 'opinion' to an applicant, nor required to obtain and furnish*

any 'opinion' or 'advice' to an applicant. The reference to 'opinion' or 'advice' in the definition of 'information' in section 2(f) of the Act, only refers to such material available in the records of the public authority......."

11. Moreover, the appellant has requested for non-specific information like "all documents", speculative information etc. hence, the CPIO's response to approach the State Government cannot be faulted. The Appellant is reminded that filing the request on similar or same subject matter with the CPIO by a mere inter play of words will not change the narrative of the case which has been already decided by the Commission. He is therefore strongly advised to desist from filing repetitive RTI Applications on the same grievance as his future appeals/complaint on the same matter are liable to be summarily dismissed. The Respondents are also advised to take reference of the instant decision while dealing with any future RTI Applications of the Appellant on the same subject matter. In view of the above, the Commission finds no scope of intervention in the matter. Accordingly, the appeals are dismissed.

Copy of the decision be provided free of cost to the parties.

Sd/-

(Anandi Ramalingam) (आनंदी रामलिंगम)
Information Commissioner (सूचना आयुक्त)
दिनांक/Date: 21.03.2025

Authenticated true copy

Sharad Kumar (शरद कुमार)
Dy. Registrar (उप पंजीयक)
011-26180514
Addresses of the parties:

1. The CPIO
Union Public Service Commission,
US & CPIO, (RTI Cell), Dholpur
House, Shahjahan Road,
New Delhi110069

2 Kamal Naagar

Annexure of Second Appeals

Sl. No.	Second Appeal No.
1	CIC/UPSCM/A/2024/105269
2	CIC/UPSCM/A/2024/105342
3	CIC/UPSCM/A/2024/105330
4	CIC/UPSCM/A/2024/105386
5	CIC/UPSCM/A/2024/105264
6	CIC/UPSCM/A/2024/105265

केन्द्रीय सूचना आयोग
CENTRAL INFORMATION COMMISSION

Recomendation(s) to PA under section 25(5) of the RTI Act, 2005:-

Nil